



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 24 जनवरी, 2005/4 माघ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

प्राधिसूचना

[शिमला-171] 002, 24 जनवरी, 2005

संख्या एल०एल०आर०डी०(४)-21/2004-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-1-2005 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश

3303-राजपत्र/2005-24-1-2005--1,487.

(3549)

मूल्य : एक रुपया।

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक 17) को वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,  
सचिव (विधि)।

2005 का अधिनियम संख्यांक 2

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन)  
अधिनियम, 2004**

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 23-1-2005 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (2004 का 9)  
का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित  
रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2004 है। संक्षिप्त ना  
और प्रारम्भ

(2) यह 15 मई, 2004 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2004 का 9

2. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 50 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— धारा 50-क  
का जोड़ना।

1972 का  
10

“50-क. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का उत्पादन और इसकी परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों का अन्तरण.—(1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से ही हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड उत्सादित हो जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उत्पादन की तारीख से ही—

(क) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के अध्यक्ष सहित सदस्यों का पद धारण करना समाप्त हो जाएगा ;

(ख) सभी सम्पत्तियां, निधियां और शोध्य रकमों, जो हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड में निहित हैं या उसके द्वारा वसूली योग्य हैं, प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी और उसके द्वारा वसूली योग्य होंगी ; और

(ग) ऐसी सभी देनदारियां जो हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी।

(3) इस धारा की कोई भी बात हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अधीन प्रत्याभूत उधार या डिबेंचरों की बाबत राज्य सरकार की देनदारियों को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उत्पादन से ठीक पहले की गई सभी संविदाएं, करार और अन्य लिखत और जिनमें बोर्ड पक्षकार है या जो बोर्ड के पक्ष में हैं, प्राधिकरण द्वारा, क साथ या क लिए की गई समझी जाएंगी।

- (5) सभी बाद, अपीलें या अन्य विधिक कार्यवाहियां जो हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध, उप-धारा (1) के अधीन इसके उत्पादन से ठीक पहले, संस्थित हैं या जो संस्थित की जा सकती थीं, प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी।

**स्पष्टीकरण.**—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए विधिक कार्यवाहियों के अन्तर्गत भूमि अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन कोई कार्यवाही सम्मिलित है।

- (6) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के सभी कर्मचारी उप-धारा (1) के अधीन इसके उत्पादन की तारीख से ही प्राधिकरण के कर्मचारी हो जाएंगे और प्राधिकरण में सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर पद धारित करेंगे और इस रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनकी सेवा निबन्धन और शर्तों, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण द्वारा परिवर्तित नहीं कर दी जाती है।

- (7) उप-धारा (6) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के किसी भी कर्मचारी ने, उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उत्पादन की तारीख से ठीक बाद के तीन मास के अवसान से पूर्व किसी भी समय प्राधिकरण को, प्राधिकरण का कर्मचारी न बनने के अपने आशय की, लिखित में नोटिस द्वारा, सूचना दी हो तो वह प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं रहेगा और ऐसे उपदान, भविष्य निधि और सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी उसे हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के नियमों या अनुमोदन (ऑथोराइजेशन) के अधीन इसके उत्पादन के ठीक पहले साधारणतया अनुज्ञेय हैं।

- (8) यदि कोई ऐसा विवाद या ऐसी शंका उद्भूत होती है कि इस धारा के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की कौन सी सम्पत्तियां, अधिकार या देनदारियां प्राधिकरण को अन्तर्गत की गई हैं या बोर्ड के अधीन सेवारत कर्मचारियों में से, किन्हें प्राधिकरण के कर्मचारी के रूप में माना जाना है, तो ऐसे विवाद या शंका को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।”।

2004 के  
अध्यादेश  
संख्यांक 2  
का निरसन  
और  
व्यावृत्तियां।

3. (1) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2004 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

**Act No. 2 of 2005.**

**THE HIMACHAL PRADESH HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 2004**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 23RD JANUARY, 2005)

**AN  
ACT**

*to amend the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 (Act No. 9 of 2004).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Amendment) Act, 2004.

Short title  
and  
commen-  
cement.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 15th day of May, 2004.

9 of 2004 2. After section 50 of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004, the following new section shall be added, namely:—

Addition  
of section  
50-A.

**“50-A. Abolition of the Himachal Pradesh Housing Board and transfer of its assets and liabilities.—**(1) On and with effect from the date of establishment of the Authority under section 3 of this Act, the Himachal Pradesh Housing Board established under the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972 shall stand abolished.

10 of 1972

(2) On and with effect from the date of abolition of the Himachal Pradesh Housing Board under sub-section (1)—

- (a) the members including the Chairman of the Himachal Pradesh Housing Board shall cease to hold office ;
- (b) all properties, funds and dues which are vested in or realizable by the Himachal Pradesh Housing Board shall vest in and be realizable by the Authority; and

- (c) all liabilities which are enforceable against the Himachal Pradesh Housing Board shall be enforceable against the Authority.
- (3) Nothing in this section shall affect the liabilities of the State Government in respect of loans or debentures guaranteed under Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972.
- (4) All contracts, agreements, and other instruments entered into immediately before the abolition of the Himachal Pradesh Housing Board under sub-section (1) and to which the Board is a party or which are in favour of the Board shall be deemed to have been entered into by, with or for the Authority.
- (5) All suits, appeals or other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the Himachal Pradesh Housing Board, immediately before its abolition under sub-section (1), shall be continued or instituted by or against the Authority.

*Explanation.*—For the purpose of this sub-section, legal proceedings includes any proceeding under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 1 of 1894).

- (6) All employees of the Himachal Pradesh Housing Board shall, on and from the date of its abolition under sub-section (1), become employee of the Authority, and shall hold office in the Authority on the same terms and conditions of service and shall continue as such unless and until their terms and conditions of service are altered by the Authority with the previous approval of the State Government.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), where any employee of the Himachal Pradesh Housing Board, by notice in writing given to the Authority at any time before the expiry of three months next following the date of abolition of the Himachal Pradesh Housing Board under sub-section (1), has intimated his intention of not becoming an employee of the Authority, he shall cease to be an employee of the Authority and shall be entitled to get such gratuity, provident fund and other retirement benefits as are ordinarily admissible to him under the rules or authorization of the Himachal Pradesh Housing Board immediately before its abolition.
- (8) If any dispute or doubt arises as to which of the properties, rights or liabilities of the Himachal Pradesh Housing Board transferred to the Authority or as to which of the employees

serving under the Board are to be treated as employees of the Authority under this section, such dispute or doubt shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

3. (1) The Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

**Repeal of  
Ordinance  
No. 2 of  
2004 and  
savings.**

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

